for promotion of Food Processing Industries. One of the schemes envisages financial assistance for setting up FPTC in rural areas. The scheme envisages entrepreneurship development and transfer of technology for rural processing of agricultural raw materials into food products, wherein "hand on" experience is provided to the trainees for operating and managing a small unit.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Loss of fruits and vegetables in Punjab and Uttar Pradesh

1951. SHRI MOHINDAR SINGH KALYAN: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details regarding loss of fruits and vegetables every year due to non-availability of food processing industries in Punjab and Uttar Pradesh; and

(b) the steps being taken by Government in the regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) Although no survey has been conducted to assess the loss of fruits & vegetables in Punjab & Uttar Pradesh, it is estimated that quality deterioration of loss in value that takes place is about 25 to 30% in some fruits and vegetables due to inadequacy of post harvest infrastracture and perishability of the produce. However, since substantial quantities of fruits and vegetables are utilised in house-hold and unorganised sector for preservation etc., the net unutilised quantity may not exceed 5%.

(b) The Government provides financial assistance to create facilities for pre-cooling and processing etc. which has been found useful in reduction of post harvest losses.

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति में परिवर्तन

1952. **श्री राम जेठमलानी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी 1991 की नीति में व्यापक परिवर्तन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब से लागू किया जाएगा;

(ग) क्या नए परिवर्तनों के माध्यम से नए परमिट जारी किए जाने पर रोक लगाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय कितनी फर्में कार्यरत हैं और उनमें से प्रत्येक का कार्यकाल कब खत्म होने जा रहा है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलिप राय): (क) और (ख) गहन समुद्री मत्स्यन नीति-1991 को रद्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) 1991 की नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति के तहत कोई नई मंजूरियां जारी नहीं की जा रही हैं। 106 जलयानों के आशयपत्र वैध हैं, जिनमें से 95 जलयानों के प्रचालन हेतु अनुमतिपत्र/परमिट जारी किए गए हैं। संयुक्त उद्यम के तहत 49 जलयानों के प्रचालन हेतु अनुमति पत्र जारी किए गए हैं जिनमें से इस समय 21 जलयान चल रहे हैं। **ये अनुमतिपत्र जलयानों के कार्यकाल तक वैध हैं। लीजिंग के तहत 46 जलयानों के प्रचालन हेतु परमिट जारी किए गए हैं, जिनमें से इस समय 10 चल रहे हैं। इनमें से अंतिम परमिट की अवधि वर्ष 2000 में समाप्त हो जाएगी।**

1952 Accord between J&K and the Central Government

1953. SHRI SHIV CHARAN SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of clauses of the 1952 Accord between Jammu and Kashmir and the Central Government, which were superceded by the 1975 Accord;

(b) what are the details of changes the Government of J&K is aiming at; and